(b) if so, the names of such States which are most affected alongwith the damage caused to the crops during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 till date;

(c) whether any 'Action Plan' has been envisaged by the Central Government in the Eighth Five Year Plan period to combat this menace; and

(d) if so, the detajls thereof particularly in the States of Rajasthas and Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) No comprehensive studies have been made regarding the exact extent of losses to crops due to pests and other diseases in the states. However, generally the incidence of pests and diseases during last three years has been noticed in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhara Pradesh, Tamil Nadu, Karnatka, Kerala, Orissa, Assam and Mizoram.

(c) and (d) During VIII Plan, Government is implementing a comprehensive Central Sector Integrated Pest Management (IPM) Scheme. Under this Scheme, emphasis is being given on training of State Extension Workers and Farmers in the farmer's fields so that they can effectively adopt IPM approach to maximise crop production.

In the State of Orissa, 13 Districts namely; Balasore, Bolangir, Cuttack, Dhenkanal Ganjam, Kalahandi, Keonjhar, Karaput, Mayurbhanj, Phulbani, Puri, Sambalpur, Sundergarh have been identified for implementing IPM in rice during 1994-95 Similarly in Rajasthan, 4 Districts namely; Banswara, Bundj, Dungarpur, Gaganagar and one District namely; Sriganganagar have been identified for implementing IPM in rice and cotton respectively during 9994-95.

पशुओं की खाल का व्यर्थ जाना

7147. **श्री सोमपाल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मृत पशु गृह न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 18 लाख पशुओं की खालें बेकार चली जाती हैं –

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा अन्य समितियों ने देश भर में मृत पशु गृहों की स्थापना हेतु कई बार संस्तुति की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमें विदेशों से भारी मात्रा में पशुओं की खालों का आयात करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक रूप से मरने वाले करोड़ों मवेशियों तथा जानवरों की खालों का उपयोग करने के लिए ऐसे गृहों की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय-बद्ध योजना बनाई है और उस योजना के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतराम): (क) कच्चे चमड़े और खालों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट (1986) में अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रतिशर्ष 8.9 मिलियन गोपशु और 9.3 मिलियन मेष सदृश पशुओं की खालें निकाली नहीं जाती।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं 1992–93 के दौरान 37581.85 मिलियन रुपए के

निर्यात की तुलना में 2543.59 मिलियन रुपए के कच्चे चमड़ तथा खालों, बिना तैयार किये चमड़े और तैयार चमड़ा उत्पादों का आयात किया गया। इस प्रकार इन उत्पादों का आयात निर्यात का 6.7% है जिसका मुख्य कारण निर्यात बाजार की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना था।

(घ) से (च) कृषि मन्त्रालय 8वीं पचवर्षीय योजना के दौरान 10 करोड़ रुपए के परिव्यय से पशुशव उपयोगिता केन्द्रों तथा चर्म निस्कचन एककों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भी मृत पशुओं की खाल निकालने उनका उपयोग करने के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत उपकरण तथा मशीनरी निर्माण-कार्य के लिए 100% सहायता अनुदान दी जाती है और वैद्युत जल, ढुलाई तथा सफाई करने जैसी सुविधाओं के लिए आंशिक रूप से सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

निम्नकोटिकृत मृदा को उर्वर बनाने हेतु जीव-गतिकी

7148. **श्री सोमपाल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "बायोडाइनेमिक्स टू रिवाइज डीग्रेडिड साइल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसमें वर्णित प्राकृतिक उर्वरकों के माध्यम से कृषि-उत्पादन को बढ़ाने की विधियों के संबंध में कोई अध्ययन किया है, अथवा करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो भारत के पर्यावरण के अनुकूल ऐसी विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) इनमें कौन-कौन से प्रयोग सरकार भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानती है और इस संबंध में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताराम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ड़) न्यूजीलैंड में प्रचारित की जा रही बायोडाइनामिक कृषि तकनीकों का अध्ययन करने और भारतीय स्थितियों में इसकी व्यावहारिकता का पता लगाने के लिये कृषि वैज्ञानिकों का एक दल न्यूजीलैंड भेजने का प्रस्ताव है।

उच्च नस्ल के मवेशियों का समाप्त होना

7149. **श्री सोमपाल :**
श्री शारदा महन्ती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पाए जाने वाले मवेशियों विशेषकर गायों की कई परम्परागत नस्लें समाप्ति के कगार पर हैं अथवा समाप्त हो चुकी हैं ;

(ख) क्या आलमबादी, बिंगापुरी, खटियालों, पुल्लिकुल्लम और बांगुर नस्ले उस सूची में शामिल हैं ;

(ग) देश में इनके अतिरिक्त कितनी और ऐसी नस्लें हैं जिनका पूर्ण अथवा आंशिक ह्रास हो रहा है ;

(घ) क्या सरकार के पास सभी महत्वपूण गोवंश नस्लों की सूची सहित ऐसा कोई रिकाड उपलब्ध है जिसमें उनकी विशेषताओं का विस्तृत रूप से वणन किया गया है ;

(ड) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) इन परम्परागत नस्लों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और